Press Clipping

The Resource Centre

Publication : United Bharat
Date : Friday, 04 February, 2011
Edition : Lucknow
Page : Front + 11

'पर्यावरण मानदंड लागू किया जाये'

नई दिल्ली, ०३ फरवरी (एजेंसियां)। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की अनुमति दी जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पर्यावरण अनुकूल प्रगति की वकालत करते हुए कहा कि पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए उचित नियामक मानदंड लागू करने ...शेष पृष्ठ ११ पर

'पर्यावरण मानदंड...

के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लाइसेंस परमिट राज नहीं लौटने पाए।

उन्होंने कहा कि मानदंडों का उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने वालों से कीमत वसूलने का सिद्धात भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मानदंड बनाना ही काफी नहीं है। उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए, जो अक्सर मुश्किल होता है। दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक २०११ के अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि किसी भी सतत विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति का केंद्रीय सिद्धात यह है कि आर्थिक पहलुओं का फैसला करने वाले सभी लोगों या संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे पर्यावरण अनुकूल बातों को हमेशा ध्यान में रखें।

इस शिखर बैठक में अफगानिस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक और सेशल्स के राष्ट्रपति भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। सिंह ने कहा, हमें ऐसी ढाचागत नियामक नितिया बनानी होंगी जो पर्यावरण को क्षति पंहुचाने वाले आचरण पर रोक लगा सके। नियामक मानदंडों को बना कर और उन्हें लागू करके हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक देशों को उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को पाने की पक्की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए जिससे कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।सिंह ने कहा कि भारत, चीन और कई अन्य विकासशील देशों ने प्रदूषण उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य और विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में अगर हमें वैश्विक जड़ता तोड़नी है तो २०२० के लिए तय किए गए कोपेनहेगन उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को हासिल करने के वास्ते औद्योगिक देशों को स्पष्ट प्रतिबद्धतता दर्शानी होगी।प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया कि औद्योगिक देशों की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अगर अपना सारा का सारा ग्रीनहाउस उत्सर्जन भी रोक दे तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह विश्व के कुल उत्सर्जन का सिर्फ चार प्रतिशत ही है।